प्रेषक - रवि शंकर राय, विषय - अर्थशास्त्र
दिनांक - 09-11-2020, वर्ग - BA 3rd

प्रश्न - सोवियत संघ की 'नवीन आर्थिक नीति' की प्रमुख विशेषताएँ बताएँ। क्या आप इस विचार से सहमत हैं कि नई आर्थिक नीति ने 'संक्रमण कालीन मिश्रित अर्थव्यवस्था' का प्रतिनिधित्व किया?
Bring out the main feature of New Economic policy of Soviet Union. Do you agree with the view that the New Economic policy represented a transitional mixed economy?

उत्तर - सामरिक साम्यवाद की नीति द्वारा सोवियत सरकार ने अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों (कृषि, उद्योग, श्रम एवं व्यापार) पर अपना एकाधिपत्य स्थापित कर लिया था। इस नीति के कारण न केवल समूची अर्थव्यवस्था अस्त-व्यस्त हो गई है; अपितु किसानों और मजदूरों के बीच मैत्री संबन्ध (जिन पर बोल्शेविक क्रांति आधारित थी) भी बिगड़ गए। गृह युद्ध के समाप्ति पर सोवियत सरकार ने सामरिक साम्यवाद की नीति का परित्याग करते हुए 'मिश्रित आर्थिक नीति' का अनुसरण किया, जिसे आर्थिक इतिहासकार 'नवीन आर्थिक नीति' की संज्ञा देते हैं। इसमें तीन बातों पर बल दिया गया —

① प्रत्येक कीमत पर उत्पादन की मात्रा बढ़ाना।

(ii) राजनीतिक संकट से बचाव अर्थात किसानों और मजदूरों के आपसी सम्बन्धों में सुधार।

(iii) राष्ट्रीय तन्त्र-मण्डल के प्रमुख केन्द्रों (विशाल-स्तरीय उद्योग, साख, मुद्रा, परिवहन और कर-प्रणाली) को हाथ में रखते हुए उनके द्वारा उत्पन्न नई ऐंजी-वादी शक्तियों का राज्य के अधिकतम कल्याण के लिए प्रयोग।

सोवियत सरकार की नवीन आर्थिक नीति कोई पूर्व-निश्चित या विधिपूर्वक निर्मित नीति नहीं थी, अपितु देश की परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित नीति थी। बेकोव (Baykov) के शब्दों में, "नई आर्थिक नीति के प्रारंभ में वे उपाय स्पष्ट नहीं थे, जिनके द्वारा उद्देश्यों एवं कार्यों को नई आर्थिक प्रणाली के सुनिश्चित रूप में ढाला जाना था। संक्रमणकाल में सरकारी एवं प्राइवेट आर्थिक कार्य-कलापों के बीच समझौता की अपरिहार्य कीमत के रूप में। प्रयास एवं त्रुटि की पद्धति अंगीकार की गई थी।"

नई आर्थिक नीति की विशेषताएँ - सोवियत सरकार की नवीन आर्थिक नीति की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित प्रकार थी —

(1) अनिवार्य अधिग्रहण नीति का परित्याग ⇒

सोवियत सरकार ने अनिवार्य अधिग्रहण की नीति का परित्याग कर दिया तथा इनके स्थान पर कृषि कर लगाया जिसका भुगतान अनाज के रूप में करना पड़ता था। कृषि कर का निर्धारण करते समय जोत के आकार के साथ-साथ कृषक-परिवार के आधार का आकार का ध्यान रखा जाता था। 'कर' का भुगतान करने के बाद किसान के पास जो अनाज बचता था, उसे खुले बजार मे बेचा जा सकता था। नई आर्थिक नीति के अन्तर्गत किसानों को सामुदायिक तथा पारिवारिक कृषि पद्धतियों से किसी एक को चुनने का अधिकार दिया गया, किसानों की उनकी भूमि पर अधिकार स्वीकार किया गया तथा अनाज के व्यापार पर से सरकारी एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। सरकार की परिवर्तित कृषि नीति के सम्बन्ध मे लेनिन ने कहा था, " अनाज की अनिवार्य वसूली के स्थान पर कृषि-कर लगाने का प्रश्न मुख्यतः राजनीतिक है। इसका उद्देश्य कृषकों और श्रमिकों का आपसी सम्बन्ध सुधारना है। हम समाजवादी क्रांति की रक्षा तभी करते हैं, जबकि हम किसानों से मिल रहे हैं। यह आवश्यक है कि मध्यवर्गीय किसानों को आर्थिक दृष्टि से संतुष्ट रखा जाये तथा खुले बजार की पुनः स्थापना की जाए। अन्यथा श्रमिकों की सत्ता कायम रखना असंभव है हो जायेगा

प्रारंभ में कृषि-कर प्रतिगामी प्रकृति का था, किन्तु बाद में इसे प्रगतिशील बना दिया गया, जिसका भार बड़े किसानों पर अधिक पड़ता था।

(2) औद्योगिक प्रशासन का विकेन्द्रीकरण - साम्यवाद की नीति के अन्तर्गत औद्योगिक प्रशासन के अत्यधिक केन्द्रीयकरण के कारण औद्योगिक प्रशासन का विकेन्द्रीकरण करना था। इस उद्देश्य के प्रति के लिए केवल विशालस्तरीय और प्रमुख उद्योग ही सरकारी स्वामित्व एवं नियंत्रण में रखे गये। छोटे उद्योगों का अराष्ट्रीयकरण करके उन्हें पुराने उद्यमियों को लौटा दिया गया। पूँजी, कौशल एवं व्यावसायिक अनुभव जुटाने के उद्देश्य से विदेशीयों को नए उद्यमों की स्थापना एवं संचालन हेतु आमन्त्रित किया गया। सरकारी और निजी पूँजी के सहयोग से कुछ संयुक्त उपक्रम भी स्थापित किए गए। 1924 में 88.4 प्रतिशत औद्योगिक संस्थाएँ निजी उद्यमियों, 3.1 प्रतिशत सहकारी समितियों तथा 8.5 प्रतिशत सरकारी स्वामित्व एवं नियंत्रण के अन्तर्गत थी। निजी क्षेत्र के उपक्रमों में केवल 12.5 प्रतिशत श्रमिक संलग्न थे; जबकि सरकारी उपक्रमों में 84.1 प्रतिशत श्रमिक संलग्न थे।